

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1937 (श0) (सं0 पटना 52) पटना, सोमवार, 18 जनवरी 2016

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

18 जनवरी 2016

एस0 ओ0 14 दिनांक 18 जनवरी 2016—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-19529/2011 सदानंद यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य बैच वादों में पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जाँच अधिनियम 1952 (सं0-60,1952) की धारा-3(1)द्वारा प्रदत्त शिक्तयों के आलोक में वर्ष 2002 से 2006 की अवधि में कार्यान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के समापन के उपरांत अवशेष खाद्यान्न की क्षति के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली हेतु एक न्यायिक जाँच आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार के राज्यपाल त्रिसदस्यीय जाँच आयोग का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय होंगे। श्री संजय सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) एवं श्री अरूण कुमार सिंह, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा (सेवानिवृत्त) जाँच आयोग के सदस्य होंगे। श्री शिश भूषण वर्मा, संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त) जाँच आयोग के सचिव के रूप में नामित किये गये हैं।

- 2. आयोग के विचारणीय बिन्द् निम्नलिखित होंगे:-
 - क. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के बंद होने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न की क्षिति एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली के दायित्व का निर्धारण।
- 3. उक्त अधिनियम की धारा-5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) (3) (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग पर लागू होंगे।
- 4. आयोग द्वारा जाँचकर अधिसूचना की तिथि से छः माह के अन्दर प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जायेगा।

[सं० ग्रा०वि०-14(विविध) न्याय-07/2015-258459] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रमोद कुमार बिहारी, सरकार के विशेष सचिव।

18 जनवरी 2016

एस0 ओ0 15 एस0 ओ0 14 दिनांक 18 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्निलिखित अनुवाद बिहार के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[संं ग्रा०वि०-१४(विविध) न्याय-07/2015-258459] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रमोद कुमार बिहारी, सरकार के विशेष सचिव।

The 18th January 2016

S.O. 14 dated 18th January 2016—In compliance of the order passed by the Honorable High Court in the CWJC No.- 19529/2011 Sadanand Yadav & Others Versus State of Bihar and Others and other batch cases, Government of Bihar has decided to appoint aJudicial Commission of Enquiry for fixing the responsibility for the loss of residual food grain after the closing of Sampurn Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Scheme between 2002 to 2006, in exercise of powers conferred under Section 3 (1) of the Commission of the Enquiry Act 1952 (No. 60, 1952).

Now, therefore, the Governor of Bihar is pleased to constitute a three member Commission of Enquiry under the Chairmanship of Honorable Justice Mr. Uday Sinha, Retired Judge of Patna High Court. Mr. Sanjay Singh, Retired I.A.S. and Mr. Arun Kumar Singh Retired Audit and Account Service will be the member of the Commission. Mr. Shashi Bhusan Verma retired Joint secretary is nominated as secretary to Commission of Enquiry.

2. The Commission will have the following terms of reference:

a. to determine the responsibility for the lapses for the loss of food grain and for realization of equivalent amount of the same after the closure of Sampurn Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Schemes.

- 3. The Governor of Bihar is further pleased to exercise powers conferred by sub section (1) of section 5 of the said Act to direct that all the provisions of sub section (2)(3)(4) & (5) of the said section shall apply to this commission.
- 4. The Commission shall submit its report within six months from the date of issue of this notification.

[सं0 ग्रा0वि0-14(विविध) न्याय-07/2015-258459] By the order of the Governor of Bihar, Pramod Kumar Bihari, Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 52-571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in